# राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 1005/2024

डॉ. विजय शंकर पुरोहित पुत्र श्री प्रेम रतन पुरोहित, आयु लगभग 69 वर्ष, मोहता चौक, बीकानेर, वर्तमान में प्रोफेसर फार्माकोलॉजी, मेडिकल कॉलेज, चुरू।---- याचिकाकर्ता

बनाम

1. प्रधान निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, गोविंद मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर।

2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, गोविंद मार्ग, जनता कॉलोनी, मेडिकल एजुकेशन भवन, जयपुर।

3. प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, चुरू।

4. प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर।-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ताओं के लिएः- श्री एम. एस. पुरोहित, श्री अमित कुमार पुरोहित
उत्तरदाताओं के लिएः----

मानननीय न्यायाधीश श्री अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

23/01/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत, जो फार्माकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं, दिनांक 09.01.2024 (अनुलग्नक 3) के एक आदेश से उत्पन्न होती है। आदेश के अनुसार उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज, चुरू से सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीगंगानगर में स्थानांतरित कर दिया गया है। स्थानांतरण के लिए निर्धारित कारण यह है कि श्रीगंगानगर में महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा बताई गई कमियों को पूरा करने के लिए, द्वितीय वर्ष के छात्रों को अपने शैक्षणिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए फार्माकोलॉजी में प्रोफेसर और पैथोलॉजी में सहायक प्रोफेसर के पद के व्यक्ति की उपस्थिति की आवश्यकता होती है।

2. उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 06.06.2018 के अनुसार फार्माकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। उक्त विज्ञापन एनाटॉमी/फिजियोलॉजी/बायोकेमिस्ट्री/माइक्रोबायोलॉजी/फार्माकोलॉजी/पैथोलॉजी/फॉरेंसिक मेडिसिन/पीएसएम में चिकित्सा की विभिन्न धाराओं में प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर/वरिष्ठ प्रदर्शक के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए था। विज्ञापन में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि भर्ती के बाद सफल उम्मीदवारों की सेवाओं को किसी विशेष मेडिकल कॉलेज में रखा जाएगा। विज्ञापन की एक प्रति सुनवाई के दौरान अदालत को सौंपी गई है और इसे रिकॉर्ड में लिया गया है और अनुलग्नक-ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है। वह दृढ़ता से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया था और उनकी सेवाओं को केवल चुरू में सरकारी मेडिकल कॉलेज में रखा गया था। इसलिए उनका तबादला नहीं किया जा सकता है।

4. आइए पहले पुनः नियुक्ति की शर्तों को देखें। राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी भर्ती नियमों के अनुसार शिक्षण कर्मचारियों के लिए पुनः नियुक्ति जारी रखने के लिए ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष है। उक्त नियमों का सुसंगत खंड, जो खंड 6 (4) है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

"6. भर्ती के तरीके-XXX (4) सोसायटी, किसी भी समय जब स्थिति आवश्यक हो, सेवानिवृत्त कर्मियों को फिर से नियुक्त करके किसी भी पद को भर सकती है। शिक्षण कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति 70 वर्ष की आयु से अधिक नहीं रहेगी और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। ऐसे पुनर्नियुक्त व्यक्ति को समेकित वेतन घटाकर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। यदि ऐसा व्यक्ति सी. पी. एफ. से सेवानिवृत्त होता है, तो उसके मामले में सी. पी. एफ. के बराबर पेंशन को समेकित वेतन से कम कर दिया जाएगा। शासी बोर्ड की मंजूरी के बाद पुनर्नियुक्ति की जाएगी।

5. उपरोक्त खंड को ध्यान में रखते हुए, मैं याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की दलीलों के साथ खुद को यह समझाने में असमर्थ हूं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की लागू स्थानांतरण नीति के अनुसार, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता का कार्यकाल 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के लिए केवल 7 और महीने बाकी हैं, उसे इस स्तर पर विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।

6. यद्यपि प्रथम दृष्टया, सहानुभूतिपूर्ण आधार पर, तर्क विश्वसनीय प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह ध्यान में रखना होगा कि राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति, ऐसा खंड होने की स्थिति में, याचिकाकर्ता पर लागू नहीं की जा सकती है। राज्य के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी होने के नाते, उन्हें राजस्थान सोसायटी नियमों के नियमों और शर्तों पर फिर से नियुक्त किया गया है, जिसमें ऐसा कोई उदार खंड नहीं है। अन्यथा, ऐसा कोई निषेधात्मक खंड नहीं है कि प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर की पुनः नियुक्ति पर, उसे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

7. अभिलेख या अभिवचनों से यह भी कहीं नहीं पता चलता है कि याचिकाकर्ता को चुरू में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने पर चुरू से श्रीगंगानगर स्थानांतरित किया जा रहा है। इसके अलावा, यह उल्लेख करना उचित है कि एक राज्य सरकार का अधिकारी, जो नियमित नियुक्ति में है, सेवानिवृत्ति के बाद फिर से नियुक्त किए गए अधिकारी की तुलना में उच्च स्तर पर खड़ा है। इसलिए, एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस व्यक्ति के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है जो सेवा में है। इसके अलावा, यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद द्वारा किए गए निरीक्षण को देखते हुए श्री गंगानगर में मेडिकल कॉलेज में काम की आवश्यकता के कारण यहां स्थानांतरण आवश्यक हो गया है, जिसके तहत उक्त कॉलेज के शैक्षणिक मामलों को पूरा करने के लिए फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी विभागों में कमी को ठीक करने की आवश्यकता है।

8. उपरोक्त आधार में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनाया गया है और तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।

9. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा कर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक सुनील कुमार किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अँग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अँग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।